राजस्थान राज्य

बनाम

राजेन्द्र प्रसाद जैन

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 360)

22 फरवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 378-दोषमुक्ति अन्तर्गत धारा 7 और 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू। एस. 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उच्च न्यायालय ने अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की।

अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः इनकार न्यायोचित नहीं - विचारण न्यायालय का पूरे साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्याकंन विफल रहा। मामले का अपील में न्याय निणर्यन आवश्यक था - चूंकि अस्वीकृति का आदेश बगैर किसी कारण को विनिर्दिष्ट करते हुए था, मामला उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-एस. 7 और 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू एस. 13 (2) .

निर्णय- कारणों को अभिलेखन करना - चर्चा करने की आवश्यकता।

पूर्ववर्ती-का पालन करने का न्यायिक अनुशासन सर्वोच्च न्यायालय द्ववारा कानून की घोषाणाओं को किसी भी प्राधिकरण या अदालत द्ववारा किसी भी तरह से मानने से इंकार नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान 1950 - अनुच्छेद 141-न्यायिक अनुशासन।

प्रतिवादी-अभियुक्त को धारा 7 और धारा 13 (1) (घ) आर/w.s.13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजित किया गया। प्रतिवादी अभियुक्त- उत्तरदाता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 Cr.P.C. में स्वीकार किया कि उसने शिकायतकर्ता से कुछ राशि प्राप्त की थी परन्तु इस तरह का तर्क उसने प्रकरण में फंसते समय कार्यवाही के समय नहीं उठाया। विचारण न्यायालय ने उसे इस आधार पर दोषमुक्त किया कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग व स्वीकृति को साबित करने में असफल रहा। अपीलार्थी-राज्य ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 378 (1) द.प्र.स. फाइल करने के लिए अनुमति याचिका पेश की जिसे उच्च न्यायालय द्ववारा खारिज किया गया। अतः वर्तमान अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश की गई।

अपील की अनुमति दी गई और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित किया।

अभिनिर्धारित किया-

1.1 आक्षेपित आदेश व्यावहारिक रूप से बगैर किसी कारण के है ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि अभियुक्त के धारा 313 द.प्र.स. दर्ज किये गये बयान में प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से यह स्वीकार किया कि उसने शिकायतकर्ता से 2000 रूपये की राशि बकाया भुगतान के लिए प्राप्त की परन्तु इस तरह का तर्क उसने जाल कार्यवाही के दौरान नहीं लिया। [पैरा 3] [284-ए-बी]

1.2 विचारण न्यायालय को सम्पूर्ण साक्ष्य का विशलेषण कर निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता थी यदि विचारण न्यायालय द्ववारा इस सम्बन्ध में चूक की गई थी तो उच्च न्यायालय इसके लिय बाध्य था कि वह अपील को स्वीकार करता विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विधि द्ववारा उसे दिए गए दायित्वों का पालन नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को अपील करने की अनुमति दी जानी थी और उसके बाद अपील की पहली अदालत के रूप में, फिर से अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य स्वतंत्र रूप से और अपराध या अपराध के संबंध में अपने निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से मूल्याकंन करना था। ऐसा करने में न्यायालय विफल रहा है। इसमें शामिल प्रश्न तुच्छ नहीं थे। गवाही की पृष्ठभूमि में अभियुक्त की स्वीकृति का प्रभाव एवं आधिकारिक गवाहों व प्रदर्शित दस्तोवजों का अपील में न्याय निर्णयन किया जाना आवश्यक था। [पैरा 7] [284-जी-एच; 285-ए]

1.3 उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरूद्घ अपील करने की अनुमति को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया और ऐसा प्रतीत होता है कि कि पूणर्तया इस तथ्य से अनजान थे कि इस तरह के इनकार से, बरी करने के आदेश की बारीकी से जांच करने का कार्य अपीलीय न्यायालय द्वारा, एक बार और हमेशा के लिए खो दिया गया है। जिस तरह से बरी किए जाने के खिलाफ अपील की गई है उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया मामला वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। [पैरा 7] [285-बी-सी]

1.4 कारण एक क्रम में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय के स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने कारणों को सामने रखना चाहिए था, भले ही वह अपने आदेश में संक्षिप्त हो ना हो, अपने दिमाग के प्रयोग का संकेत देता हो, और भी अधिक जब इसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो। बगैर कारणों के उच्च न्यायालय के आदेश को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता। कारण हर निष्कर्ष आधार है, और इसके बिना इसका कोई औचित्य नहीं है।

[पैरा 7 और 8] [285 - सी-डी, एफ]

यू. पी. राज्य बनाम पट्टन और अन्य 2001 (10) एस. सी. सी. 607; राज्य महाराष्ट्र का बनाम विट्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण ए. आई. आर 1982 एस. सी. 1215 ; जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह और अन्य

1987 (2) एस. सी. सी. 222; राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य 2003 (7) सुप्रीम 152-पर भरोसा किया।

1.5 कारण निष्कर्षकर्ता के मस्तिष्क से सम्बन्धित विवाद और उस पर आये निर्णय व निष्कर्ष का जीवंत संबंध है। प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी, ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971 (1) ऑल ईआर 1148) में लॉर्ड डेनिंग एमआर ने कहा, "कारण बताना अच्छे प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है"। अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री (1974 आईसीआर 120) (एनआईआरसी) में यह देखा गया: "कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है।" कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग से संबंधित विवाद और उस पर आए निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत संबंध हैं। यह अपनी चुप्पी से, इससे न्यायालयों के लिए अपना अपीलीय कार्य करना या निर्णय की वैधता तय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव हो जाता है। तर्क का अधिकार एक सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है; कारण कम से कम न्यायालय के समक्ष मामले पर दिमाग लगाने का संकेत देने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक दिए गए आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का गूढ़ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

तर्क का अधिकार एक सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है; कारण कम से कम न्यायालय के समक्ष मामले पर दिमाग लगाने का संकेत देने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक दिए गए आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का गूढ़ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है। तर्क का अधिकार एक सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है; कारण कम से कम न्यायालय के समक्ष मामले पर दिमाग लगाने का संकेत देने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक दिए गए आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का गूढ़ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

आम तौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत। [पैरा 9] [285-एच; 286-ए-डी] उड़ीसा राज्य बनाम। धनीराम लुहार 2004(5)एससीसी 568 ब्रीन वी. समामेलित अभियांत्रिकी संघ 1971 (1) सभी E.R.1148 और अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड v. क्रेबट्री 1974 आई. सी. आर. 120 (एन. आर. सी.) संदर्भित।

2. इस प्रकार के कारणों को वर्णित करने की आवश्यकता न्यायिक रूप से अनिवार्य माना गया है। उच्चतम न्यायालय द्ववारा कानून की घोषणा का पालन करने के लिए न्यायिक अनुशासन। न्यायालय या किसी भी प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय द्ववारा की गई कानूनी घोषणाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 141

क्रिमिनल अपीलीय क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील 360/2008

(राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 23/2002 में पारित अन्तिम निर्णय और आदेश दिनांक 27-06-2006 से उत्पन्न)

नवीन कुमार सिंह, शाश्वत गुप्ता और अरूणेश्चर, अपीलार्थी के लिए

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(1) के संदर्भ में अपील करने की अनुमति के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है। (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.')।

3. पृष्ठभूमि के तथ्यों को संक्षेप में नोट करने की आवश्यकता है: प्रतिवादी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 और 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा (संक्षेप में) 'कार्य')। विद्वान विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा ने सेशन प्रकरण संख्या 8/2001 में बरी करने का निर्देश दिया। बरी करने का निर्देश देने का मूल कारण यह था कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और स्वीकृति को साबित करने में विफल रहा है और जिस दिन शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने का दावा किया था, उस दिन आरोपी के पास कोई काम लंबित नहीं था। अपीलकर्ता राज्य ने अपील करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। इसे आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कम से कम यह कहें तो यह आदेश व्यवहारिक रूप से अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में। पी.सी. प्रतिवादी ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि उसे कुछ बकाया राशि के भुगतान के लिए शिकायतकर्ता से 2,000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन ट्रैप कार्यवाही के दौरान ऐसी कोई दलील नहीं दी गई।

4. नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

5. इस तरह के आवेदन को निपटाने के दौरान अपनाए जाने वाले पैरामीटर इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में निर्धारित किए गए हैं।

6. सीआरपीसी की धारा 378 में दोषमुक्त होने की स्थिति में अपील की अनुमति देने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। धारा 378 की उपधारा (1) और (3) इस प्रकार है:

> "378(1) उप-धारा (2) में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर और उप-धारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीलीय आदेश या पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में।
>
> (3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी भी अपील पर उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना विचार नहीं किया जाएगा।"

7. विचारण न्यायालय को पूरे साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना था और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था। यदि विचारण न्यायालय ने इस संबंध में चूक की थी, तो उच्च न्यायालय अपील पर विचार करके ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य था। इस मामले के तथ्यों पर

विचारण न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जैसा कि कानून द्वारा उसे सौंपा गया था। उच्च न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों में अपील करने की अनुमति दे देनी चाहिए थी और उसके बाद अपील की पहली अदालत के रूप में, स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की फिर से समीक्षा करनी चाहिए थी और आरोपी के अपराध या अन्यथा के संबंध में अपने निष्कर्ष निष्पक्ष रूप से पारित करने चाहिए थे। वह ऐसा करने में विफल रहा है. इसमें शामिल प्रश्न मामूली नहीं थे. सरकारी गवाहों की गवाही और प्रदर्शित दस्तावेजों की पृष्ठभूमि में अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के प्रभाव के कारण अपील में निर्णय की आवश्यकता पड़ी। उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है, और ऐसा लगता है कि वह इस तथ्य से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि इस तरह के इनकार से, अपीलीय मंच द्वारा दोषमुक्त करने के आदेश की बारीकी से जांच की गई है। एक बार और हमेशा के लिए खो गया. उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उसमें बहुत कुछ अपेक्षित नहीं है। कारण किसी क्रम में स्पष्टता लाते हैं। न्याय के स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने कारणों को सामने रखना चाहिए था, भले ही वह अपने आदेश में संक्षिप्त क्यों न हो, अपने दिमाग के प्रयोग का संकेत देता हो; और भी अधिक जब इसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च

न्यायालय के आदेश को टिकाऊ नहीं बना दिया है। ऐसा ही विचार यूपी में भी व्यक्त किया गया। बनाम बट्टन और अन्य (2001 (10) एससीसी 607)। लगभग दो दशक पहले महाराष्ट्र राज्य बनाम विट्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण (एआईआर 1982 एससी 1215) में अपील की अनुमति देने के अनुदान के लिए एक आवेदन से निपटाने के दौरान बोलने के आदेश की वांछनीयता पर प्रकाश डाला गया था। ऐसे मामलों में कारण बताने की आवश्यकता को न्यायिक रूप से अनिवार्य माना गया है। जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह और अन्य में इस दृष्टिकोण को दोहराया गया था। (1987 (2) एससीसी 222)। इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा का पालन करने के लिए न्यायिक अनुशासन को, किसी भी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा किसी भी बहाने से नहीं छोड़ा जा सकता है, चाहे वह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों न हो, भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 141 (संक्षेप में) से बखबर 'संविधान')।

8. तर्क हर निष्कर्ष की धड़कन है और इसके बिना यह बेजान हो जाता है। (देखें राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य (2003 (7) सुप्रीम 152)।

9. प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी, ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971 (1) ऑल ई.आर. 1148) में लॉर्ड डेनिंग एम.आर. ने कहा, "कारण बताना अच्छे प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है"। अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री (1974

आईसीआर 120) (एनआईआरसी) में यह देखा गया: "कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के समान है।" कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग से संबंधित विवाद और उस पर आए निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत संबंध हैं। यह अपनी चुप्पी से, न्यायालयों के लिए अपना अपीलीय कार्य करना या निर्णय की वैधता तय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बना सकता है। तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है; कारण कम से कम न्यायालय के समक्ष मामले में दिमाग लगाने का संकेत देने के लिए पर्याप्त है। एक अन्य तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का गूढ़ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

10. उपरोक्त स्थिति को उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार (2004(5) एससीसी 568) में उजागर किया गया था।

11. इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जाता है, और मामले को उसके पास भेज दिया जाता है। उच्च न्यायालय इस मामले को नए सिरे से उठाएगा और कानून के अनुसार इसका निपटारा करेगा। लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सत्येन्द्र सिंह चौहान, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।